DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

----------DATED----------

राजधानी से दूर की जाएगी आवास की समस्या : पुरी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि गरीबों, किसानों और मध्यम वर्ग की आवास की समस्या दूर करने के लिए दिल्ली के मास्टर प्लान-2041 में प्रविधान होगा। फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) बढ़ाकर दोगुना किया जाएगा। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 10 लाख लोगों को पक्का मकान दिया जाएगा। लैंड पूलिंग योजना में किसानों को आने वाली समस्याएं दूर करने के लिए संसद में विधेयक पेश किया जाएगा।

हरदीप पुरी

प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि लैंड पूलिंग से 75 लाख, अनधिकृत कालोनियों में मालिकाना हक देने के लिए प्रधानमंत्री उदय योजना से 50 लाख और 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' योजना से 10 लाख दिल्लीवासियों को अपना मकान मिलेगा। कुल 1.35 करोड़ लोगों को इसका लाभ होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 635 झुग्गी बस्ती हैं। इनमें से केंद्र सरकार के विभागों की जमीन पर बसी 376 झुग्गी बस्तियों के लोगों को 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' के तहत फ्लैट दिए जा रहे हैं। कालकाजी में लाभार्थियों को घर की चाभी दी गई है। जेलरवाला बाग व कठपुतली कालोनी में भी फ्लैट लगभग तैयार हैं। इस योजना का लाभ देने के लिए 210 बस्तियों में लोगों से आवेदन लिए गए हैं। शेष झुग्गी बस्तियों में भी अगले वर्ष मार्च तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा।

दिल्ली सरकार गरीबों को नहीं दे रही मकान

उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार अपनी जमीन पर बसी 291 झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को मकान देने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। प्रधानमंत्री उदय योजना की तरह इन झुग्गीवासियों को मकान देने के लिए भी केंद्र सरकार प्रक्रिया पूरी करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार वर्ष 2041 मास्टर प्लान में दोगुना एफएआर का प्रविधान करने के लिए डीडीए एक्ट में संशोधन किया जा रहा है। इससे दिल्ली के मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी। डीडीए और ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में पार्किंग की समस्या दूर की जाएगी। निगम चुनाव के बाद यह काम शुरू होगा। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी व अन्य भाजपा सांसद मौजूद थे।

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली ।
गुरुवार, 1 दिसंबर 2022

नए इलाके जुड़ने से बदली 'गार्डन' की तस्वीर

वॉर्ड नंबर 219
दिलशाद गार्डन
68,357

आप – प्रवीण कसाना

बीजेपी – बीएस पवार

कांग्रेस - विनोद कुमार

Rajesh.Saroha@timesgroup.com

परिसीमन के बाद दिलशाद गार्डन वॉर्ड की सूरत काफी बदल गई है। वॉर्ड में एक तरफ सुंदर नगरी जी और एच ब्लॉक की झुग्गी बस्ती के अलावा दिलशाद कॉलोनी, ताहिरपुर गांव और लैप्रोसी कॉलोनी जैसे इलाकों को शामिल किया गया है, वहीं दूसरी तरफ जगतपुरी एक्सटेंशन और जीटीबी हॉस्पिटल कैंपस इस वॉर्ड से हट गए हैं। नए इलाके जुड़ने से दिलशाद गार्डन वॉर्ड काफी बदल गया है।

वॉर्ड में दिलशाद गार्डन के एमआईजी, एलआईजी और जनता फ्लैट्स के अलावा जीटीबी एनक्लेव के डीडीए फ्लैट्स, सुंदर नगरी झुग्गी बस्ती, लैप्रोसी कॉलोनी और ताहिरपुर गांव का इलाका आता है। यहां वैश्य, एससी और ब्राह्मण वोटर्स के अलावा पहाड़ी और पूर्वांचली वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। यहां बंगाली और साउथ इंडियंस वोटर्स की भी अच्छी खासी संख्या है। बीजेपी ने इस वॉर्ड से पूर्व निगम पार्षद बीएस पवार को मैदान में उतारा हुआ है। वह स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन के अलावा दो बार डेम्स के चेयरमैन और दो बार जोन के डिप्टी चेयरमैन भी रहे हैं। पहाड़ी वोटर्स पर उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। वह इस वॉर्ड से 3300 वोटों से जीते थे।

वॉर्ड वॉर

उन्होंने कांग्रेस से तीन बार निगम पार्षद रहे चौधरी अजीत सिंह को हराया था। बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष विजय सहदेव एनसीपी से टिकट देकर घड़ी के निशान पर चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। पार्टी से टिकट न मिलने से वह नाराज हैं।

आम आदमी पार्टी ने यहां से प्रवीण कसाना को चुनाव मैदान में उतारा है। खुद को बहारी बताए जाने पर वह कहते हैं कि पिछले कई साल से वह दिलशाद गार्डन और पॉकेट में रह रहे हैं। इतना ही नहीं, वह आरडब्ल्यूए फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं। फेडरेशन में 25 आरडब्ल्यूए आती हैं। वह 12 हजार एससी, 10-12 हजार मुस्लिम वोटर्स और 15 हजार ओबीसी वोटर को साधने में जुटे हुए हैं। वह एमसीडी में फैले भ्रष्टाचार, साफ सफाई और पार्कों की बदतर हालत जैसे मुद्दों पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे विनोद कुमार को भरोसा है कि इस चुनाव में कांग्रेस का परंपरागत वोटर मुस्लिम और एससी वापसी करेगा। वह पूर्व निगम पार्षद की नाकामियों को गिनाते हुए कहते हैं कि पूरे 5 साल में इलाके में कोई काम नहीं हुआ। यही वजह है कि इलाके के पार्कों की हालत बद से बदतर हो गई है।

वॉर्ड के मुद्दे

पार्कों की खराब हालत, बदतर साफ सफाई, पार्किंग की समस्या, बिल्डिंग विभाग में फैला भ्रष्टाचार और सुंदर नगरी की झुग्गी बस्ती में विकास न होना हैं इस वॉर्ड के प्रमुख मुद्दे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
THURSDAY, DECEMBER 1, 2022

Puri Outlines BJP Master Plan For Resolving Housing Issues

Says Amendments Will Let People Make Additional Constructions

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: To woo the urban voters ahead of the high-stake municipal polls in the capital, Union housing and urban affairs minister Hardeep Singh Puri on Wednesday said the Centre had incorporated the provision of regeneration and redevelopment of old houses and group housing societies in Delhi Master Plan of 2041 and proposed to increase the floor area ratio.

Addressing a press conference at the BJP headquarters along with the party MPs from Delhi, Puri said once the new master plan was implemented, residents would be able to make additional construction and add dwelling units and toilets to cater to bigger families, while the housing societies could have improved layouts and bigger parking lots.

"The government is not only working to rehabilitate slum dwellers but also taking measures to redevelop group housing societies, provide better housing to the middle class through various schemes of DDA and to our farmer brothers residing in rural parts of the capital," said Puri.

The housing minister claimed that Delhi Master Plan 2041, in the final stage now, was going to be a visionary document to usher in a new era of development. "In 2021, the floor area ratio was enhanced to 200. The regeneration of FAR (after demolishing and rebuilding) is envisaged in the master plan 2041 at a fixed rate ranging from 260 to 340, depending on the plot size," Puri said.

For the poor, he said, the Centre has started working on the redevelopment of 210 JJ clusters to fulfil its promise of providing modern houses under Pradhan Mantri Awas Yojana (urban). Delhi Development Authority has completed physical surveys of these slums and collected application forms from the residents in the digital mode to provide them housing in multistoreyed apartment complexes with modern facilities, he added. The survey of 166 more slums will start immediately after the conclusion of the municipal polls and will be completed by March 2023, the minister said.

BJP has made in situ development of slum clusters and rehabilitation of its residents a major poll plank and has been showcasing the recent allotment of 3,024 flats in Kalkaji to the residents of the neighbouring Bhumiheen camp as its major achievement. Party workers have taken slum dwellers from various clusters across the city on a visit to these flats in the past few weeks.

Singh said Delhi currently has 675 slum clusters, of which 376 with 1.7 lakh households have come up on the land belonging to DDA and other central government agencies. He, however, alleged that the Delhi government had yet to start the redevelopment work on 299 clusters falling under the jurisdiction of Delhi Urban Shelter Improvement Board.

"DDA has embarked upon a mission to fulfil the housing aspirations of Delhi residents. The Modi government has already constructed 3,024 flats in Kalkaji where the possession of EWS units is under way," Puri said. "In the next few months, we are going to complete the Jailorwala Bagh project to rehabilitate 1,675 JJ dwellers and another in Kathputli Colony."

On the land pooling policy, the minister said 7,087 applications had been received from land-owners expressing willingness to participate in the scheme and around 7,400 hectares had been pooled. To resolve teething problems such as mutation of land, stamp duty and contiguity of 70% pooled land, the government has proposed amendments in DD Act 1957, which will be placed before Parliament soon, Puri assured.

TOI

Hardeep Singh Puri with senior party members at BJP's headquarters on Wednesday

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली
। गुरुवार, 1 दिसंबर 2022

RS----------DATED----------

सबको मिलेगा घर: बीजेपी

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेश किया हाउसिंग स्कीम का पूरा खाका

■ प्रमुख संवाददाता, नई दिल्ली

एमसीडी चुनाव जैसे-जैसे पास आ रहा है, सियासी हलचल उतनी ही तेज हो रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने दिल्ली मॉडल को लोगों के सामने परोस रहे हैं, वहीं बीजेपी इस मॉडल को काउंटर करने के लिए नए-नए दांव चल रही है। इसी कड़ी में बुधवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि अगली जनगणना के समय दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ से अधिक होगी। इतनी बड़ी आबादी में से बीजेपी का प्लान 1.37 करोड़ लोगों को घर देना है।

उन्होंने कहा कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या 1.67 करोड़ से अधिक है। लेकिन, अगली जनगणना में जनसंख्या 2 करोड़ से भी ज्यादा होगी। ऐसे में दिल्ली में झुग्गी कलस्टर में रहने वाले लोगों को 10 लाख से अधिक मकानों की जरूरत होगी। बीजेपी ने झुग्गियों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान देने का जो वादा किया था, उस वादे को निभाया भी है।

कालकाजी एरिया की झुग्गियों में रहने वाले करीब 3 हजार से अधिक लोगों को वहीं फ्लैट दिए गए हैं। अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले करीब 50 लाख लोगों को पीएम उदय योजना के तहत मकान मिलेंगे। डीडीए की जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है, उससे करीब 75 लाख लोगों को मकान मिलेगा। इस तरह अगली जनगणना में दिल्ली की जितनी जनसंख्या होगी, उसमें करीब 1.37 करोड़ लोगों को मकान मिलेंगे।

पुरी ने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों को पक्का करने का जो मसला था, वह 2015 से ही चल रहा है। दिल्ली सरकार हर बार कोई न कोई बहाना कर इस समस्या को टालती रही है। 2021 में जब इस पर दिल्ली सरकार से बातचीत हुई, तो पता चला कि ग्राउंड सर्वे ही नहीं हुआ है। तब यह मामला केंद्र सरकार ने अपने हाथों में लिया और पीएम उदय योजना के तहत अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के मालिकाना हक देने की स्कीम चलाई गई और अब इस स्कीम के तहत लोगों को फायदा भी मिल रहा है। उन्होंने आजादी के वक्त दिल्ली की जनसंख्या का भी जिक्र किया और कहा कि तब दिल्ली की आबादी सिर्फ 7 लाख ही थी। शरणार्थियों के आने के बाद दिल्ली की जनसंख्या 21-22 लाख हो गई और अब जितनी जनसंख्या है उसके बारे में सभी को पता ही है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि इतनी बड़ी जनसंख्या को पक्का मकान उपलब्ध कराना चुनौती तो है, क्योंकि दिल्ली का जितना एरिया है उतने एरिया में बढ़ी हुई आबादी को मकान देना चुनौती है। लेकिन, बीजेपी ने पूरा प्लान तैयार कर रखा है। दिल्ली में 675 झुग्गी बस्तियां हैं, जिसमें से 210 झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान उलब्ध कराने के लिए आवेदन ले लिए गए हैं।

लैंड पूलिंग स्कीम के तहत 7 हजार 400 हेक्टेयर जमीन पर ग्रुप हाउसिंग डिवेलप किया जाएगा। इतने लैंड डिवेलप होने के बाद करीब 75 लाख लोगों को मकान की समस्या खत्म हो जाएगी। लैंड पूलिंग के तहत ग्रुप हाउसिंग डिवेलप करने में जो अड़चने आ रही थीं, उन्हें खत्म करने के लिए डीडी एक्ट-1957 में संशोधन किया जा रहा है। ताकि यह स्कीम असानी से लागू हो सके और लोगों को मकान मिल सके।

PTI

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी का प्लान दिल्ली की 2 करोड़ जनसंख्या में से 1.37 करोड़ लोगों को घर देना है। इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे

बीजेपी का प्लान

- एमसीडी चुनाव से बीच केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को काउंटर करने के लिए बीजेपी का दांव
- अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले करीब 50 लाख लोगों को पीएम उदय योजना के तहत मकान देने की योजना
- डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत करीब 75 लाख लोगों को मकान का वादा

Hardeep Singh Puri

AAP DID NOTHING FOR RESIDENTS OF SLUMS UNDER ITS WATCH: UNION MIN PURI'S ATTACK

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Union housing and urban affairs minister Hardeep Singh Puri on Wednesday accused the Aam Aadmi Party (AAP)-led Delhi government of not doing any work with regards to the in-situ rehabilitation of slums on land under its jurisdiction, pointing to central schemes for the redevelopments of slums. The minister also spoke about various provisions in the draft Delhi master plan 2041, scheduled to be notified next year, will have.

Puri's attack on the AAP came amid a heated war of words between the BJP and the AAP ahead of the municipal corporation polls, scheduled for December 4.

The BJP, which has controlled the corporation for the last 15 years and is eying a fourth successive term in the civic body, is reaching out to slum residents – considered a strong support base for the AAP – by pitching the work done by the Centre, especially in housing-related issues, just like it did before the assembly elections in 2020.

Speaking at a press conference, Puri noted that Prime Minister Narendra Modi had on November 2 inaugurated 3,024 new flats for poor families as part of a slum rehabilitation project in south Delhi's Kalkaji Extension.

"Similar projects are under construction at Jailorwala Bagh and Kathputli Colony. There are 675 slum clusters in Delhi of which 376 are on central government land. The Delhi Development Authority (DDA) has completed the survey of 210 clusters to identify beneficiaries and the remaining work will commence after the municipal elections and will be completed by March 2023. Unfortunately, no work has been done in the 299 slum clusters which are under the Delhi government," the Union minister said.

AAP spokespersons did not respond to requests for comment.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--- पंजाब केसरी ----------DATED----------

केंद्र का नया दांव, 'जहां झुग्गी वहां मकान'

एमसीडी चुनाव

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली में नगर निगम चुनाव के बीच केंद्र सरकार ने राजधानी की कॉलोनियों और रिहायशी इलाकों के कायाकल्प को लेकर अपनी योजना सामने रखी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि जल्द ही केंद्र की योजना के तहत दिल्ली की अवैध कालोनियों को रेगुलराइज किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम उदय योजना से दिल्ली के 50 लाख लोगों को फायदा होगा। दिल्ली की आबादी लगातार बढ़ रही है, इसे देखते हुए केंद्र सरकार लगातार गरीबों को घर दे रही है।' पुरी ने कहा कि 'दिल्ली की आबादी अगली जनगणना में दो करोड़ से ज्यादा की होगी। अब इस आबादी में हमारी जो योजनाएं हैं उनमें जहां झुग्गी जहां मकान योजना के 10 लाख लाभार्थी होंगे। अवैध कॉलोनियों को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मसला लटकाकर रखा। हमें उम्मीद है कि 50 लाख नागरिकों को अवैध कॉलोनियों को वैध करने से फायदा मिलेगा।' उन्होंने कहा कि करीब 1 करोड़ 35 लाख दिल्ली के नागरिकों को रीडेवलेपमेंट का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि 2040 तक दिल्ली की कुल आबादी 3 करोड़ तक पहुंच जाएगी।

केन्द्रीय मंत्री हरदीप पुरी, भाजपा सांसद हंसराज हंस, रमेश विधूड़ी, मनोज तिवारी, डा. हर्षवर्धन और प्रवेश वर्मा के साथ संवाददाता सम्मेलन के दौरान। (छाया : प्रेट्र.)

प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन से कालका जी में बनाए गए ईडब्ल्यूएस के 3 हजार से अधिक फ्लैट्स की चाबी सौंपी है। जेलरवाला बाग में भी एक प्रोजेक्ट है, जिसमें बड़ी संख्या में फ्लैट्स बनाए गए हैं। इसके अलावा कठपुतली कॉलोनी व कुछ अन्य प्रोजेक्ट्स भी हैं। केंद्र सरकार लगातार गरीबों के लिए काम कर रही है।' -(पृष्ठ 4 भी देखें)

1 दिसम्बर • 2022 राष्ट्रीय सहारा

दिल्ली में 50 लाख झुग्गीवासियों को मिलेगा पक्का घर : पुरी

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान से चार दिन पहले आज यहां केन्द्र में भाजपा की सरकार में शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री हरदीप पुरी ने ऐलान किया कि राजधानी में 50 लाख से अधिक झुग्गी वालों को उनके स्थान पर पक्के मकान बना कर दिये जाएंगे। पुरी ने भाजपा के केन्द्रीय कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के पुनर्विकास से एक करोड़ 35 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे।

■ कहा, इससे राष्ट्रीय राजधानी के पुनर्विकास से एक करोड़ 35 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में विज्ञान भवन से कालका जी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाए गए 3 हजार से अधिक फ्लैट्स की चाबी सौंपी। जेलरवाला बाग में भी एक परियोजना है, जिसमें बड़ी संख्या में फ्लैट्स बनाए गए है। इसके अलावा कठपुतली कॉलोनी एवं कुछ अन्य परियोजनाएं भी है। केंद्र सरकार निरंतर गरीबों के लिए कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि 2011 के जनगणना के अनुसार दिल्ली की आबादी 1.67 करोड़ मानी गई थी। अब जब अगली जनगणना होगी तो दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से अधिक ही होगी। जो हमारी योजनाएं अभी लागू है, जहां 'झुग्गी वहां मकान' के तहत 10 लाख लाभार्थी होंगे।

पुरी ने एमसीडी के 'भाजपा घोषणापत्र का हवाला देते हुए कहा कि हमने घोषणापत्र में भी कुछ फिगर दिए है। जो अनियमित कॉलोनी है, उनमें 'पीएम उदय' योजना के तहत 50 लाख नागरिकों को लाभ मिलेगा। 'जहां झुग्गी-वहां मकान' योजना के लगभग 10 लाख लाभार्थी होंगे। लैड पूलिंग योजना के अंतर्गत 75 लाख लाभार्थी होंगे। कुल मिलाकर दिल्ली की करीब दो करोड़ आबादी में से 1 करोड़ 35 लाख नागरिक पुनर्विकास का लाभ उठाएंगे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी दिल्ली गुरुवार 1.12.2022

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा हमारी सरकार दिल्ली में डीडीए के मकानों पर बढ़ा रही है एफएआर

दिल्ली में मिडिल क्लास वालों के लिए भी पीएम मोदी का तोहफा: हरदीप पुरी

केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा हमारी सरकार दिल्ली में 'जहां झुग्गी वहां मकान' दे रही है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने कालका जी में लोगों को घरों की जब चाबिया दी तो उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। इसके अलावा दिल्ली के कई इलाकों में झुग्गी के बदले मकान देने की योजना पर काम चल रहा है। पीएम उदय योजना ने दिल्ली में 50 लाख लोगों को फायदा होगा। *एमसीडी चुनावों के बीच हरदीप पुरी ने पंजाब केसरी के मेट्रो एडिटर सतेन्द्र त्रिपाठी व डिप्टी चीफ सुरेन्द्र पंडित से विशेष बातचीत में कहा कि दिल्ली के लोगों को समझना होगा कि उनके लिए बेहतर कौन है?*

पुराने डीडीए फ्लैटों में बदलाव से लाखों लोगों को मिलेगा फायदा...

भाजपा ने एमसीडी चुनावों के लिए अपना संकल्प पत्र पेश कर दिया है, जिसमें गरीबों को जहां झुग्गी वहां फ्लैट देने का काम भी शुरू कर दिया है। यह तो गरीबों की बात थी दिल्ली के मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी हम योजना लेकर आए हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (डीडीए) फ्लैट्स में फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) को बढ़ाने जा रही है। ऐसे में 'जब घर छोटा और परिवार बड़ा हो, तो फ्लोर एरिया रेश्यो को बढ़ाने की जरूरत है।' उन्होंने कहा कि 2041 के मॉडल के मुताबिक घर को बड़ा करने में दिक्कत नहीं आएगी। दिल्ली के मिडिल क्लास के लोगों के लिए यह प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा तोहफा होगा। 'आज दिल्ली की बहुत बड़ी संख्या जनता डीडीए फ्लैट में रहती है, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहती है। दिल्ली में जिनका अपना घर है, उनका एफएआर डबल करने का निर्णय मोदी सरकार ने लिया है। अब दिल्ली के लोगों को अपना घर बड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता है। हरदीप पुरी ने कहा कि अपने घर को रेनोवेट करने में जो एफएआर है, उसको डबल करने के निर्णय के बाद कोई आपको डंडा दिखाने नहीं आ सकता। कोई गलत डिमांड करने नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों यानी 2004 से 2014 के बीच शहरों का विकास नहीं हो रहा था, उसके बावजूद देश के छोटे शहरों व कस्बों से लोग काम की तलाश में दिल्ली में लगातार आ रहे थे और जहां उन्हें जगह मिल रही थी, वहीं झुग्गी बना कर रह रहे थे, एक समय ऐसा आया जब स्थिति बेकाबू हो गई, लेकिन उसका हल नहीं ढूंढा गया। यहां यह बता दें कि शहरीकरण के लिए जहां पिछली सरकार ने इन 10 सालों में जहां सिर्फ 1.57 लाख करोड़ रुपए ही आवंटित किए वहीं मोदी सरकार ने अपने पिछले आठ साल के कार्यकाल में 12 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। दिल्ली पर दबाव कम करने के लिए मेट्रो का जाल बिछाया। अब एनसीआर को विकसित कर रही है ताकी दिल्ली पर दबाव कम हो सके। इसके लिए रैपिड रेल का सहारा लिया जा रहा है। मेरठ से एक घंटे से भी कम समय में लोग दिल्ली आ सकेंगे, अभी अपनी गाड़ी से नोएडा पहुंचने में ही डेढ़ घंटा लग जाता है। जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद स्थिति में अमूलचूल परिवर्तन होगा।

लैंड पुलिंग को लेकर सरकार गंभीर...

हम केवल शहरी विकास की ही बात नहीं करते हैं बल्कि गांव-देहात का भी डवलपमेंट कर रहे हैं। गांव-देहात में लैंड पुलिंग योजना को लेकर सरकार बहुत गंभीर है। लैंड पुलिंग की समस्या से निजात दिलाकर वहां के लोगों को भी ये सुविधा दी जा रही है। ये दिल्ली की बड़ी समस्या थी, जिसके निपटारे की जरूरत थी। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि करीब 1 करोड़ 35 लाख दिल्ली के नागरिकों को रीडिवेलपमेंट का लाभ मिलेगा। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन जमीन उतनी ही है। इसीलिए दिल्ली के लिए 2041 तक का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। जिसमें गरीबों के लिए पक्के मकान और अवैध कॉलोनियों के रीडेवलपमेंट का काम शामिल है। उन्होंने कहा कि लैंड पूलिंग योजना के अंतर्गत 75 लाख लाभार्थी होंगे। सरकार ने अनधिकृत कॉलोनी की समस्या का निपटारा कर दिया। डीडीए और हाउसिंग सोसाइटी की समस्या का समाधान हो गया। यह पीएम मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। हरदीप पुरी ने कहा कि दिल्ली के किसान भाईयों समेत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लैंड पूलिंग की समस्या झेलनी पड़ती है। भाजपा ने संसद में इससे संबंधित जल्द ही एक विधेयक लाए गीता कि किसानों की लैंड पूलिंग की समस्या खत्म हो सके।लैंड पूलिंग योजना से 75 लाख लोग लाभान्वित होंगे। केन्द्रीय योजना के तहत प्रधानमंत्री उदय योजना के माध्यम से दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को रेगुलराईज किया जाएगा। इससे50 लाख लोग लाभान्वित होंगे। जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले 10 लाख परिवारों को पक्के मकान दिए जाएंगे।

सत्येन्द्र जैन एकमात्र जेल में रहते हुए आम आदमी पार्टी के हैं मंत्री...

एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में एक मात्र केजरीवाल सरकार के मंत्री सतेन्द्र जैन ही है जोकि जेल में रहते हुए मंत्री बने हुए हैं। अभी तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन जेल में मौज की जिंदगी जी रहे हैं। सोसैटीवी फुटेज में सत्येंद्र जैन जेल में अपनी बैरक में ही मसाज का लुत्फ उठाते हुए दिखाई देते हैं। बैरक के अंदर अच्छा भोजन करते नजर आते हैं। अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए फाइल भी देख रहे हैं। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि इससे अच्छी क्या बात हो सकती है।

आप पार्टी के खालिस्तानियों से संबंध जगजाहिर हैं...

पंजाब में बुधवार को विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे किसानों पर भगवंत मान की सरकार ने लाठी चार्ज कर दिया। हरदीप सिंह ने इस मुद्दे पर आप सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहले जब केन्द्र ने कृषि के तीन कानून बनाए थे, तब सबसे पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार ही थी जिसने विधानसभा में इसे पारित करने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में यही केजरीवाल उनके साथ जाकर धरने पर बैठे गए, अब उन्हीं की पार्टी की पंजाब सरकार उन्हीं किसानों पर लाठी चलवा रही है। खालीस्तानी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह तो जगजाहिर हो चुका है कि पंजाब के चुनाव में खालिस्तानियों के साथ उनके रिश्ते रहे हैं। केजरीवाल खालिस्तान समर्थकों के प्रति नरम हैं। यह स्पष्ट है कि केजरीवाल का खालिस्तान समर्थकों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, उन्होंने पिछले पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान उग्रवादी के आवास पर एक रात बिताई थी। केजरीवाल या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने पटियाला हिंसा में शामिल खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहां तक की खुद को भगत सिंह कह रहे हैं यह तो उन शहीद की शहादत का अपमान है।

सीएम-एलजी के बीच रार नई नहीं...

दिल्ली के उपराज्यपाल से आए दिन होने वाली रार पर केन्द्रीय हरदीप पुरी ने कहा कि यह सब जानबूझ कर विवाद पैदा करने के लिए किया जाता है। वर्तमान उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के कामों की जब समीक्षा की तो कितनी ही खामियां सामने आईं जिसके बाद दोनों के बीच तल्खी बढ़ी है। लेकिन अगर इनसे पहले वाले एलजी से भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ही ऐसी है अपना काम नहीं करना और झूठ की राजनीति करना है। दिल्ली की जनता को यह समझना पड़ेगा कि मुफ्त की बिजली लेकर उन्होंने क्या-क्या खोया है? इसका सीधा सा असर दिल्ली के विकास पर पड़ा, उनके बच्चों के लिए केजरीवाल सरकार ने एक भी कालेज या विश्वविद्यालय खड़ा नहीं किया, नए स्कूल नहीं बनाए, हां कुछ स्कूलों में क्लासरूम जरूर बना दिए हैं, जिसे दिखा-दिखा कर दिल्ली को दिल से खेला जा रहा है। आठ सालों में केजरीवाल सरकार ने कोई नया अस्पताल नहीं बनाया, उनका मोहल्ला क्लीनिक ठप हो चुका है। कोरोना के दौरान मोहल्ला क्लीनिकों ने दम तोड़ दिया।

— फोटो: मिहिर सिंह

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER THE HINDU DATED 1-12-2022

'Centre's redevelopment projects likely to benefit at least 1.35 crore people in city'

Union Housing and Urban Affairs Minister Hardeep Singh Puri says more flats for slum dwellers to be ready soon; he also blamed the Delhi govt. for delaying the redevelopment and rehabilitation work in 299 JJ clusters under its control

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Union Minister for Housing and Urban Affairs Hardeep Singh Puri on Wednesday said the various redevelopment projects of the Central government, including the "Jahan Jhuggi Wahin Makaan" and the PM-UDAY schemes, are expected to benefit at least 1.35 crore residents of Delhi.

Mr. Puri said the "Jahan Jhuggi Wahin Makaan" scheme will benefit 10 lakh slum dwellers in Delhi, while around 50 lakh residents of unauthorised colonies will benefit from PM-UDAY. Parallelly, at least 75 lakh Delhiites will benefit from the Delhi Development Authority's (DDA) land pooling policy (LPP), he added.

Union Minister Hardeep Singh Puri at the BJP headquarters in Delhi on Wednesday. R.V. MOORTHY

DDA Act to be amended

Making the announcement on the LPP ahead of the voting for the Municipal Corporation of Delhi (MCD) elections on December 4, Mr. Puri said the Centre was going to bring in an amendment to the Delhi Development Act, 1957, in its efforts to hasten the land pooling scheme's implementation.

The LPP was notified on two occasions (in 2013 and 2018), however, the DDA has faced multiple roadblocks in its implementation on the ground due to two eligibility conditions - minimum participation of 70% of the landowners and 70% contiguous land.

One of the proposed amendments – first announced by Mr. Puri in early March, prior to the now-cancelled polls to the three erstwhile civic bodies – will make pooling of land mandatory for the remaining landowners if the minimum participation rate of 70% is achieved. The other amendment grants power to the Centre to declare land pooling mandatory, even if the minimum criteria of 70% participation and 70% contiguity are not achieved.

"About 7,100 applications have been received from land owners and around 7,400 hectares have been pooled till date," he added.

Hits out at AAP

At a press conference, Mr. Puri also accused the AAP-led Delhi government for delaying the redevelopment and rehabilitation work in the 299 JJ clusters under its control.

"Of the total 675 clusters in Delhi, 376 are on DDA and Centre's land and we finished the survey in 210 of them, and applications from slum dwellers have also been received. Work in the remaining 166 clusters will be completed soon," Mr. Puri said, adding, "We will also step in and start work in the 299 clusters under the Delhi government after the MCD elections if there is any further delay from their [Delhi government] side."

The Delhi government did not respond to Mr. Puri's charges at the time of filing this report.

The Union Minister also said provisions will be made in the Delhi Master Plan-2041 to help people redevelop their old buildings with enhanced floor area ratios. "The above provisions would cater to an increase in dwelling unit size/number of dwelling units and toilets to cater to an increase in family size and population," he told reporters. "The provisions would also cater to improvements in layout, accessibility through the road network plan, and improvements in parking."

Talking about the 3,024 flats for slum dwellers inaugurated by Prime Minister Narendra Modi earlier this month, Mr. Puri said more such projects were in advanced stages. "Jailorwala Bagh project with 1,675 flats will be completed in the next few months, while another project in Kathputli Colony will be ready next year," he added.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली ■ बृहस्पतिवार, 1 दिसंबर 2022

NAME OF NEWS अमर उजाला 2 ----------DATED----------

मास्टर प्लान 2041 पर होगा काम: पुरी

केंद्रीय मंत्री ने दो करोड़ की आबादी की जरूरतों के हिसाब से विकास की बात कही

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को रिहायशी इलाकों के कायाकल्प का खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि एमसीडी की सत्ता हासिल होने पर दिल्ली के गरीबों, किसानों और मध्यम वर्ग को बेहतर आवासीय सुविधा देने के लिए भाजपा मास्टर प्लान 2041 लाएगी।

इसमें फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) दो गुना होगा। आवास के साथ पार्किंग सुविधा भी बेहतर होगी। लैंड पूलिंग पॉलिसी, प्रधानमंत्री उदर्य समेत जहां झुग्गी वहीं मकान योजना से हर दिल्लीवासी को आवास मुहैया कराया जाएगा। लैंड पूलिंग की समस्या खत्म करने के लिए भाजपा संसद में जल्द ही विधेयक भी लाएगी।

पुरी ने बताया कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने ईडब्ल्यूएस के करीब तीन हजार फ्लैट लोगों को दिए। इसी तरह के फ्लैट जेलरवाला बाग में बनेंगे। अनधिकृत कालोनियों को भी अधिकृत किया जाएगा। मोदी सरकार गरीब एवं मध्यम वर्ग की आवास की समस्याओं का समाधान करने के लिए कटिबद्ध है। केंद्र सरकार ने तय किया है कि दिल्ली में झुग्गियों में रहने वाले लोगों को मकान दिया जाएगा।

75 लाख लोगों को लैंड पूलिंग पॉलिसी से होगा फायदा

झुग्गी में रहने वाले दस लाख परिवारों को मिलेंगे पक्के मकान

पुरी ने बताया कि 1970-80 के दशक के दौरान डीडीए और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट छोटे थे। पार्किंग का भी उचित इंतजाम नहीं था। परिवार बढ़ने से अब लोगों का पार्किंग व कमरे की परेशानी हो रही है, इसीलिए मास्टर प्लान 2041 से मध्यम वर्ग को राहत दिलाई जाएगी। एमसीडी चुनाव जीतने पर भाजपा पुनर्विकास की नई परिभाषा लिखेगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWS the pioneer D 1-12-2022

No power can stop AAP from winning MCD polls: CM

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Led by Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, the Aam Aadmi Party on Wednesday turned the last leg of its MCD election campaign into an impressive show of strength.

After conducting a door-to-door campaign on Tuesday, Kejriwal took out a massive road show on Wednesday and addressed a Jansabha after that. The road show began from Malka Ganj Chowk near Kamla Nagar and went to Ghanta Ghar Chowk with the entire stretch engulfed in hues of blue, yellow and white.

Addressing the jansabha, Kejriwal , "No power can stop AAP from winning MCD elections, because people of Delhi will vote for the party that wants to work and not for the party that wants to stop all the work," he said , adding, " These people (BJP) stopped the Mohalla Clinic and CCTV project files,. I faced great difficulties in getting the projects cleared."

He said Delhi LG VK Saxena stopped free yoga classes, but now classes are being run on donations . " I won't let a single project stop in Delhi,: he said.

Charging the BJP-led MCD of turning the national capital into a garbage heap, he said ," It pains my heart to see Delhi be engulfed by garbage. Despite being the CM I have no power to clean garbage because MCD is under BJP.

Delhiites gave us the responsibility of schools, hospitals, electricity, water, we fixed everything and provided free healthcare and electricity to everyone.

Public gave BJP one job, they had to look after the garbage but even in 15 years they could not clean Delhi. BJP has deployed 7 CMs, 1 Dy CM and 17 Cabinet Ministers to fight against an Aam Aadmi like me. Had they done some work in the last 15 years, BJP would not need to bring all its bigwigs from across the country in a municipal election," he said.

The Chief minister said when the public wanted to know the what the BJP has done in its 15-year-long MCD tenure, Home Minister Amit Shah said Kejriwal did not give us any funds to carry out development work. " Look at his audacity. The Home Minister is asking for funds from a state government. We gave 1 lac crores to the MCD, but BJP turned all of it into dust.

Despite getting all the funds their leaders cry, yell and howl on the streets of Delhi asking for money. The Centre doesn't give Delhi Government any funds, you don't see me begging like them."

Gave us the job of fixing schools and hospitals, the result is front of you; now give us the chance to fix garbage management," said Kejriwal

Kejriwal said the MCD poll is not about any political party but about the prestige and progress of Delhi. " These people have turned Delhi into such a herbage dump that it is now difficult for a common man to live here.

You gave us the job of fixing schools, hospitals, electricity, water and governance, you have the results in front of you. World class schools, hospitals, Mohalla Clinics, free electricity-water, faceless and doorstep services. But garbage management is under the MCD. We have to come together and solve this garbage problem," he said..

He went on to add, "It pains my heart to see Delhi be engulfed by garbage. Despite being the CM, I have no power to clean this garbage because of the division of powers.

It has been 15 years since they have been running the MCD, yet they failed at handling garbage. If you let us run the MCD, then we will be able to clear out the garbage very easily. Give me 5 years in MCD, we will give you a sparkling clean Delhi."

Reaching out to the MCD employees, Kejriwal said their salary will come into their accounts in the first week of the month from now, no matter how he did it. "I will arrange the funds and make it possible." he said.

BJP extorting money from traders: Sisodia

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Deputy Chief Minister Manish Sisodia accused the BJP on Wednesday of extorting money from traders in Krishna Nagar in east Delhi and said AAP convener Arvind Kejriwal would help them get rid of the "curse".

Sisodia held marches in various wards of Laxmi Nagar, Krishna Nagar and Patparganj and interacted with the people on the civic issues that were being faced by them.

The AAP leader said drains in most of the colonies were choked and overflowing.

"Water accumulates in the streets and causes many diseases, but the BJP has completely ignored all this over the years. The BJP has never considered garbage management as their duty in the past five years," he said. Addressing the public in Krishna Nagar, Sisodia alleged that the BJP extorted money from the traders and imposed conversion charges arbitrarily, but it had been unable to provide a proper parking facility in the past 15 years.

"Along with this, it conducted various inappropriate sealing operations and tried to shut down many businesses. This impacted many families," he said.

'Jahan Jhuggi Wahin Makan to benefit 10L slum dwellers'

New Delhi: Union Housing and Urban Affairs Minister Hardeep Singh Puri on Wednesday said nearly 1.35 crore Delhi residents, including 10 lakh slum dwellers, will benefit from various redevelopment initiatives, including 'Jahan Jhuggi Wahin Makan', undertaken by the Centre in the city.

Holding the AAP led Delhi Government responsible for delay, the Union Minister alleged that there are 299 JJ clusters where the responsibility for rehabilitation has been cast on Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB), which falls under Delhi government and unfortunately, no work has been carried out so far.

"In Delhi there are 675 clusters, out of which 376 clusters (comprising 1.72 lakh households) are on DDA and Central Govt lands. DDA has completed survey of 210 clusters, wherein application forms of the dwellers have been taken through digital mode. The Survey work of remaining 166 will commence immediately after municipal elections and will be completed by March 2023," Puri said while addressing a press conference.

"The planned re-development and rehabilitation work is not restricted to only Jhuggi Jhopri clusters in the national capital but also covers work done for group housing societies, housing for middle class through various schemes of DDA, for farmer residing in the rural areas," said Puri. *SR*

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS दैनिक भास्कर ----------DATED---------1-12-2022

दो बड़ी घोषणा • एमसीडी चुनाव से पहले केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय का तोहफा

1 10 लाख झुग्गी वालों को 3 साल में मकान

2 अब सभी मकानों की ऊंचाई भी बढ़ा सकेंगे

दिल्ली की 1.5 करोड़ आबादी को फायदा

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

एमसीडी चुनाव के पहले केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को इस घोषणा के दौरान कहा, पीएम उदय आवास योजना के तहत शहरी विकास मंत्रालय ' जहां झुग्गी वहां मकान' योजना के तहत दिल्ली में 10 लाख झुग्गी वालो को 38 मीटर में आवास बनाकर देगी। यह योजना तीन साल में पूरी होगी। एमसीडी में भाजपा सत्ता में आती है तो एमसीडी को 'जहां झुग्गी वहां मकान' नोडल एजेंसी बनाकर डीडीए और एमसीडी के जमीनों पर बनी झुग्गियों पर पीएम आवास योजना के तहत निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पुरी ने मध्यम वर्ग के लोगों को छोटी पड़ती जा रही घर में जगह को देखते हुए 1970 में बने डीडीए कालोनियों, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में में एफएआर को बढ़ाने का निर्णय लिया है। पुरी ने कहा कि जहां पर पार्किंग की सुविधा होगी वहां हम एफएआर को 240 प्रतिशत से बढ़ाकर 360 करेंगे। इससे घर का जगह लगभग दो गुना हो जाएगा और परिवार के बढ़ने के कारण छोटी पड़ती घर के आभाव में मां,पिता से बेटे को बिछड़ना नहीं पड़ेगा। पुरी ने बताया कि परिवार बढ़ने से घर छोटे होते जा रहे थे इस कारण हम जनकल्याण में इस योजना को लेकर आ रहे हैं। पुरी ने बताया कि एफएआर बढ़ने से अधिक क्षेत्र में निर्माण होने के कारण फ्लैटों की दरों में भी काफी तेजी आएगी और अनुमान है कि मकानों के कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण 90 फीसदी लोग इस योजना का लाभ उठाएंगे।

स्लम क्लस्टरों की सर्वे रिपोर्ट का काम पूरा : हरदीप पुरी

शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने ' जहां झुग्गी वहां मकान' के बारे में कहा कि दिल्ली में कुल 675 जेजे क्लस्टर है, जिसमें से 376 डीडीए और 299 डूसीब के जमीन पर बसी है। पुरी ने बताया कि हमने 'जहां झुग्गी वहां मकान' बनाने के लिए डीडीए के जमीन पर बसी 376 में से 200 से अधिक स्लम क्लस्टरों की सर्वे रिर्पोट का काम पुरा कर लिया है और हम टेंडर करने के प्रक्रिया का काउंट डाउन शुरू हो चुकी है। पुरी ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली अनियमित कालोनियों को नियमित करने के काम के लिए दिल्ली सरकार 2017 से लेकर 2020 तक कमेटी बनाने के नाम पर गुमराह करती रही, बोट बैंक बनाकर रखती रही पर हमें काम करना था इसके बाद दिल्ली सरकार से काम लेकर हम खुद सर्वे की प्रक्रिया पुरी कर अनियमित कालोनियों को नियमित किया। पुरी ने बताया कि पीएम आवास योजना में देरी नहीं की जाएगी, अगर डूसिब के जमीनों पर बसी जेजे क्लस्टर पर दिल्ली सरकार खुद 'जहां झुग्गी वहां मकान' नहीं बनाती है तो हम पहले के तरह केंद्र अधिकार के परिधी में झुग्गी में रहने वाले लोगों को जहां है वहीं घर बनाकर देगी, वही व्यवसाय देने के लिए पीएम मोदी के तरफ से हम बचनबद्ध है।

अब फ्लोर एरिया रेश्यो और उसकी कैलकुलेशन को समझिए

किसी प्रोजेक्ट का FAR बिल्डिंग का टोटल फ्लोर एरिया होता है (जिसमें बिल्डिंग के सभी फ्लोर्स द्वारा कवर किया गया स्पेस शामिल होता है) जिसे उस भूमि के क्षेत्र से डिवाइड किया जाता है, जिस पर प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। एफएआर को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या डेवेलपमेंट अथॉरिटीज डेवेलपमेंट कंट्रोल रेग्युलेशन्स (DCR) के मुताबिक तय करती हैं। यह हर शहर या इलाके में अलग-अलग हो सकती हैं।